भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4345

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 5 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन

4345. श्री अमर शंकर साबले:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संख्या की दृष्टि से एफएएमई भारतीय योजना का निष्पादन राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 के अंतर्गत परिकल्पित संख्या से बहुत ही कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मिशन के अनुसार संख्या बढ़ाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी 2020) के तहत वर्ष 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनो की 6-7 मिलियन बिक्री प्राप्त करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य है।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनो (एक्सईवी) को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2015 में फेम इंडिया स्कीम अधिसूचित की। सरकार ने ₹14,000 करोड़ की सहायता से 6 वर्षो के बदले ₹695 करोड़ के परिव्यय के साथ 2 वर्षो के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया, जैसा कि एनईएमएमपी 2020 में परिकल्पना की गई थी। इस समय, फेम इंडिया स्कीम का चरण-1 चल रहा है, जो आरंभ में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक 2 वर्षो की अवधि के लिए था, और दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक आंतिम विस्तार के साथ बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीम के क्षेत्र को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

स्कीम के अंतर्गत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में विभाग ने एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों और विशेष श्रेणी के राज्यों को इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक चोपहिया यात्री कारों और इलेक्ट्रिक तिपहियों के संयोजन में मांग प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर आधारित सार्वजनिक और साझा मोबिलिटी आरंभ करने की घोषणा की, इस ईओआई को जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिसमें विभाग को 3144 ई-बसों, 2430 ई-चोपहिया टैक्सियों और 21545 ई-तिपहिया ऑटो की आवश्यकता के साथ 21 राज्यों के 44 शहरों से 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्तमान रूचि की अभिव्यक्ति के तहत वित्त पोषण हेतु ग्यारह (11) शहरों का चयन किया गया। चुने गए शहरों को दिनांक 28 फरवरी, 2018 से पहले निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देना और आपूर्ति आदेश जारी करना अपेक्षित था। चुने गए ग्यारह (11) शहरों में से, नौ (9) शहरों ने अपनी निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है और चुने गए निविदाकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-1 में प्राप्त अनुभव के आधार पर, यह देखा गया है कि देश में पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचटना की अनुपलब्धता और लिथियम बैटरी का न होना इस स्कीम के संभावित परिणाम के साथ सहज शुरूआत में मुख्य बाधाएं हैं। मोटरों, कंट्रोलरों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अभी पूर्णतः विकसित किया जाना है। इससे लागत बढ़ती है और वाहनों के मूल्य को अप्रतिस्पर्धात्मक बनाती है।

*****